भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2245

जिसका उत्तर सोमवार, 9 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ी

2245. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान पर बढ़ती निर्भरता के फलस्वरूप क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि तथा विशेषकर विगत तीन वर्षों के दौरान देखी गई प्रवृति के आँकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ी के जोखिमों के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने हेतु कोई विशिष्ट पहल अथवा जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए हैं;

(घ) क्या कोई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और यदि हां, तो वर्ष 2023 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के ऐसे कितने अभियान चलाए गए; और

(ङ) क्या सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने तथा क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि के साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में क्यूआर कोड संबंधी धोखाधड़ियों सहित डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ियों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गईं वर्ष-वार क्यूआर आधारित धोखाधड़ियों का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ): क्यूआर आधारित धोखाधड़ी सहित भुगतान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से दो स्तरीय अधिप्रमाणन, दैनिक लेनदेन सीमा, उपयोग के मामलों को सीमित करना इत्यादि शामिल हैं।

आरबीआई और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, 'साइबर अपराध' की रोकथाम पर प्रचार आदि के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। 2023 के दौरान देश भर में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल 317 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, मार्च 2023 में 'डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह' के हिस्से के रूप में "डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ" की थीम के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू किया गया था।

एनपीसीआई ने जागरूकता अभियान भी चलाया है जिसमें कहा गया है कि "क्यूआर कोड केवल भुगतान करने के लिए स्कैन किया जाता है, प्राप्त करने के लिए नहीं" और इसे टीवी, डिजिटल, रेडियो और प्रिंट मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों से संप्रेषित किया गया है। इसके अलावा 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पंजाब, हरियाणा और असम) के 48 गांवों में एक ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित किसी भी साइबर घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर "1930" भी लॉन्च किया है। इसी तरह, दूरसंचार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (डीआईपी) और 'चक्षु' लॉन्च किया है जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संदेश को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।

******

अनुबंध ।

वित्तीय वर्ष	**घटनाओं कि संख्या**	**अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में)**
वित्तीय वर्ष 2021-22	14,625	19.35
वित्तीय वर्ष 2022-23	30,340	41.73
वित्तीय वर्ष 2023-24	39,638	56.34
वित्तीय वर्ष 2024-25*	18,167	22.22

**सितम्बर, 2024 तक*